भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2308

19.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

लोकोमोटर दिव्यांगजन के लिए जीएसटी रियायत प्रमाण पत्र को बंद करना

2308 **श्रीमती रंजीत रंजन:**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) लोकोमोटर दिव्यांगजन को वाहन खरीदने पर मिलने वाली जीएसटी रियायत को बंद करने के क्या कारण है;

(ख) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि यह निर्णय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में दिए गए नियमों और दिव्यांगजन के अधिकारों पर यूएन सम्मेलन के तहत भारत की प्रतिबद्धता का उल्लंघन करता है, यदि हाँ, तो मंत्रालय इस मुद्दे को किस प्रकार हल करने की मंशा रखता है; और

(ग) क्या सरकार ने रियायती जीएसटी दर हटाने से होने वाले वित्तीय प्रभाव या अतिरिक्त राजस्व लाभ का अनुमान लगाया है, यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लिए अनुमानित राजस्व लाभ कितना है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख): भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने पहले राजस्व विभाग की दिनांक 30.09.2019 की अधिसूचना के अनुसार, अस्थिविरूपता से पीड़ित पात्र दिव्यांगजनों को छोटी कारों के लिए वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी) रियायत प्रमाण पत्र जारी किए थे। राजस्व विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जीएसटी दरें जीएसटी परिषद, जो केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से मिलकर बना एक संवैधानिक निकाय है, की सिफारिशों के आधार पर अधिसूचित की जाती हैं, 3 सितंबर, 2025 को आयोजित अपनी 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में, परिषद ने मौजूदा चार-स्तरीय जीएसटी दर संरचना को नागरिक-अनुकूल "सरल कर" दो-स्तरीय दर संरचना में युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश की। परिषद ने अस्थि विरूपता से पीड़ित दिव्यांगजनों के लिए छोटे पेट्रोल/डीजल चालित मोटर वाहनों पर लागू जीएसटी दर में कोई बदलाव की सिफारिश नहीं की, जिस पर 18% जीएसटी लगना जारी रहा। इसके अलावा, परिषद ने छोटे पेट्रोल/डीजल चालित मोटर वाहनों पर जीएसटी दर को 28% से घटाकर 18% करने की भी सिफारिश की।

इसके बाद, भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने 08.10.2025 को अधिसूचित किया कि वित्त मंत्रालय द्वारा जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाए जाने को ध्यान में रखते हुए,

हुए, छोटी कारों पर 18% की एकसमान जीएसटी दर सभी व्यक्तियों पर लागू होती है, जिनमें अस्थिविरूपता से पीड़ित दिव्यांगजन भी शामिल हैं।

तदनुसार, जीएसटी छूट प्रमाण पत्र स्कीम के तहत अस्थिविरूपता से पीड़ित दिव्यांगजनों के लिए जीएसटी रियायत प्रमाण पत्र जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ग) : भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

****